भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2199
20 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में नीली क्रान्ति

2199. श्री चिराग कुमार पासवानः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में नीली क्रांति के तहत मत्स्य पालन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसमें शामिल लागत को संतुलित करने के लिए मत्स्य पालकों को राजसहायता प्रदान की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने मत्स्यपालन हेतु तालाब, नदी, झील खोदने और अन्य जल निकायों का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो क्या उक्त योजना बिहार में लागू है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किन जिलों में चल रही है और ग्रामीण क्षेत्र के जलीय कृषि किसानों को बाजार तक मछली ले जाने के लिए परिवहन के क्या साधन उपलब्ध हैं; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार का बिहार में मत्स्य पालन प्रशिक्षण आदि हेतु कोई महाविद्यालय या प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओएफएएचएंडडी) ने 323.12 करोड़ रु/- के बिहार सरकार के प्रस्तावों को अनुमोदित किया था और विगत में वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान कार्यान्वित नीली क्रांति पर केंद्र प्रायोजित योजना : मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन के अंतर्गत राज्य में मात्स्यिकी और जल कृषि विकास के लिए 76.80 करोड़ रु/- की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की थी जिसमें विभिन्न गतिविधियां कवर की गईं जैसे मीठे पानी की फिन फिश और प्रॉन हैचरी, इनपुट के साथ तालाब निर्माण, बीज पालन क्षेत्र, आर्द्र भूमि (वेटलैंड) में बीज संभरण, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), वेटलैंड और जलभराव क्षेत्र का विकास, खुदरा और थोक मछली बाजार और मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण तथा इसमें शामिल व्यय को संतुलित करने के लिए सामान्य श्रेणी को 40% और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को 60% सबसिडी प्रदान किया गया। इसके अलावा, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पिछले दो वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार के सभी जिलों में मत्स्य पालन और जल कृषि के विकास के लिए कुल 301.30 करोड़ रुपये की लागत से बिहार सरकार के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें परिवहन सुविधाएं जैसे आइस-बॉक्स के साथ साइकिल, आइस-बॉक्स के साथ मोटर साइकिल, आइस-बॉक्स के साथ तिपहिया वाहन, मछली बेचने के लिए ई-रिक्शा और इंसुलेटेड वाहन भी जल कृषि किसानों को प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के तहत लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार को 42.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की गई ।

(ङ): मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार के पास मात्स्यिकी के लिए कॉलेज या प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****